

## प्रेस रिलीज़

03 अक्टूबर 2019  
नई दिल्ली

### गृह मंत्री ने संविधान का मज़ाक बनाया है: पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने पश्चिम बंगाल में आयोजित बीजेपी के सेमिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रश्न उठाया है, जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकता देने और मुसलमानों को इससे अलग रखने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि जिस गृह मंत्री ने संविधान का पाबंद रहने की शपथ ली है, वही उसका मज़ाक बना रहा है। हमारा संविधान साफ तौर पर धार्मिक भेदभाव को रद्द करता है और सेक्युलरिज़्म को बरकरार रखता है, जो कि उसके मौलिक सिद्धांतों में से एक है।

अमित शाह का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) बिल पास होने के बाद हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी और वह यह विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा देश भर में एनआरसी लागू होने से पहले होगा। सरकारी तौर पर यह इस बात का सबूत पेश करता है कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल की पूरी प्रक्रिया के पीछे एकमात्र इरादा मुसलमानों के साथ भेदभाव बरतना है। अमित शाह इस स्पष्टीकरण की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते कि किस तरह भारत में रहने वाले दूसरे धर्म के विदेशी लोग शरणार्थी बन जाते हैं, और सिर्फ मुसलमान अपने धर्म के कारण घुसपैटिया हो जाता है। देश में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि शासक दल और सरकार में ऐसे ऊँचे पद पर बैठा शख्स धार्मिक नफरत का इस तरह खुला इज़हार करता हो। पॉपुलर फ्रंट का मानना है कि संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति ऐसे घमंड और गैरजवाबदेही को बर्दाश्त करना न केवल मुसलमानों, बल्कि पूरे देश और पूरी जनता जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं, के लिए तबाही का सामान होगा। अगर अमित शाह के लिए गृह मंत्री का पद संभालते समय संविधान के पालन की शपथ के कोई मायने नहीं हैं, तो उन्हें उसके प्रतिनिधित्व का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता।

ई. अबूबकर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भारत के हिंदू राष्ट्र होने के हालिया बयान के बारे में कहा कि यह भी इस धार्मिक भेदभाव का संदेश दे रहा है।

आरएसएस भले ही भारतीय मतदाताओं की छोटी सी संख्या के सहारे सत्ता तक पहुंच गई हो, लेकिन देश के बहुमत ने आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को कभी कबूल नहीं किया और न ही उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। साथ ही उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि यह बस वक्त की बात थी कि जनता की छोटी सी संख्या ने बीजेपी को विकास और तरक्की के नाम पर वोट दिया, लेकिन अब उन्होंने भी उनकी नाकाम सरकार को रद्द कर दिया है।

**डॉ० मुहम्मद शमून**

डायरेक्टर, जनसंपर्क

मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

नई दिल्ली